

## संपादकीय

सरकार के पिछले 3 व-नों के कार्यों का मूल्यांकन करने के 2 प्रकार हैं ; पहला, कृ-नि में इसके प्रमुख कार्यक्रमों और उनके प्रभावों को देखने का मूल्यांकन करना। अन्य प्रकार यह है कि भारतीय जनता पार्टी के व-र्न 2014 के घो-णापत्र को देखें और यह जांच करें की उन वादों में से कितने वादे पूरे किये गये।

भा.ज.पा. के घो-णापत्र में था कि 'भा.ज.पा. कृ-नि वृद्धि, किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता देने का वादा करती है। भा.ज.पा. कृ-नि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ाएगी, उत्पादन की लागत पर 50 प्रतिशत का न्यूनतम लाभ सुनिश्चित करके कृ-नि में लाभ बढ़ाने के उपाय, किसानों को सस्ती दर पर कृ-नि उपकरण और ऋण देना, नवीनतम कृ-नि तकनीक प्रारंभ करना एवम् अधिक पैदावार के बीजों की आपूर्ति तथा कृ-नि को मनरेगा से जोड़ने के सभी उपाय करेगी।'

3 व-र्न पूरे होने के बाद हम देखते हैं कि अपने वादों को पूरा करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं और कई योजनाएँ अभी भी एक तरफ रखी हुई हैं। अब कोई बात भी नहीं करता की किसानों को 50 प्रतिशत लाभ सुनिश्चित किया जाएगा, बल्कि अब एक नया वादा किया जा रहा है कि अगले 5 व-नों में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। इसके अतिरिक्त वास्तविक आय को दोगुनी करने की परिभा-ना भी बदलकर कुछ और कहा जा रहा है।

सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य यह था कि 2 व-नों में एक बार सभी किसानों की भूमि का स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाएगा। 14 करोड़ कार्ड जारी करने का लक्ष्य था लेकिन अभी तक केवल 6 करोड़ कार्ड की बांटे गये हैं।

जल संसाधन मंत्रालय के अधिन प्रधानमंत्री कृ-नि सिंचाई योजना के लिए एक नया लक्ष्य निदेशालय (मिशन डायरकटोरेट) बनाया गया है। सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभकारी कार्यक्रम के अंतर्गत शिघ्र पूरी होने वाली 99 परियोजनाओं की पहचान की है। 99 में से, 23 परियोजनाएँ (प्राथमिकता-1) को मार्च 2017 तक पूरा करने के लिए चुना गया था। यह परियोजनाएँ जो इस समय तक पूरी करनी थी, इनमें से वास्तव में कोई भी पूरी नहीं हुई, हालांकि बहुत सी परियोजनाएँ शिघ्र पूरी होने की संभावना है।

सरकार के पहले 3 व-नों में कृ-नि सकल घरेलू उत्पाद केवल 1.7 प्रतिशत वार्षिक बढ़ा, यह संयुक्त प्रगतिशिल गठबंधन की सरकार के पिछले 3 व-नों के दौरान प्राप्त उपलिब्ध (3.6) का आधे से भी कम है।

केंद्रीय सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर फसलों पर किसानों को बोनस देने से राज्य सरकारों को भी मना कर दिया है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त प्रगतिशिल गठबंधन - 2 की सरकार के पहले के 3 व-नों की तुलना में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्यों में पिछले व-नों की तुलना में की गई वृद्धि को भी कम कर दिया है।

किसानों द्वारा अथक प्रयास के पश्चात अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन करने के बावजूद भी गेहूं और मक्का का आयात किया जा रहा है, जिससे किसानों के लाभ में कमी आ रही है।

ई-नेम एक अन्य उपाय है। यह उपाय करने पर लाभ यह मिलता की किसी भी मंडी से कृनि जिंसों की खरीद दूर के स्थान पर भी खरीददार कर सकते थे। अभी तक 13 राज्यों में 417 मंडियां ई-नेम पोर्टल से जोड़ने का दावा किया गया है। अधिकतम मंडियों में पारंपरिक बोली से की गई बिक्रीयों को ही ई-नेम के माध्यम से किये गये कारोबार में दिखाया जा रहा है। ई-नेम के कुल रु. 15,605/- करोड़ के कारोबार में से केवल हरियाणा में ही रु. 8,237/- करोड़ का कारोबार दर्शाया जा रहा है। इस योजना को सफल साबित करने के लिये हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सभी खरीदों को ई-ट्रेडिंग कारोबार में दिखाया जा रहा है। इस प्रकार बनावटी और झूठे समाचार दिये जा रहे हैं।

सरकार ने पूर्वी राज्यों में दूसरी हरित क्रांति लाने का वादा किया था, किंतु उन क्षेत्रों में किसानों द्वारा आत्महत्या करने की घटनाओं में 4 गुणा वृद्धि हुई है। पिछले 3 वर्षों में ही 40,000 से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं, अर्थात् औसतन 34 किसान प्रतिदिन।

डेरी उत्पादक क्षेत्र में आत्महत्या की घटनाओं में कमी की जा सकती है, किंतु डेरी उत्पादक को पशुओं के लाने-जाने पर प्रतिबंध लगने के कारण अधिकतम हानि हुई है। जब भारत का डेरी उद्योग रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है तो अनावश्यक रूप से बट्टर ऑयल का आयात करके डेरी उद्योग को भी समाप्त किया जा रहा है। महारा-ट्र में किसानों द्वारा आत्महत्याएँ करने की घटनाएँ बढ़ी हैं, क्योंकि दूध का मूल्य गिरकर रु. 16/- प्रति लिटर हो चुका है।

प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना में लगभग रु. 23,000/- करोड़ किसानों से प्रीमियम के रूप में इकट्ठे होंगे, किंतु संसद में एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया कि 'खरीफ 2016 में रु. 4,270.55/- करोड़ का दावा करने के आंकड़े उपलब्ध हैं, इनमें से अभी तक बिमा कंपनियों द्वारा केवल रु. 714.14/- करोड़ के दावों का निपटान किया गया है।'

### सही 'दिशा' की ओर सामाजिक सुधारों को आजीविका सुधारों से संगठित करना

भरत डोगरा

शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में रस्सी बनाने वाले कारीगरों के किसान परिवार बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। खटिया की बुनाई और कुर्सी एवम् मूड़ा जैसे अन्य फर्नीचर तैयार करने में प्रयुक्त रस्सी बनाने के लिये शिवालिक क्षेत्र के किसानों को वहां उगने वाली भाबर घास की आवश्यकता होती है। जैसा की अन्य कारीगर क्षेत्रों में होता है, वहां भी बिचौलिये और व्यापारी कच्ची सामग्री सस्ते में खरीद लेते थे और घास को महंगी बेचकर कारीगरों को लूटते थे।

किसानों का यहू-ण रूकने वाला नहीं था यदि एक स्थानीय सामाजिक संस्था, 'दिशा' इसमें हस्तक्षेप नहीं करती। इस संस्था ने घास खरीदकर रस्सी बनाने वाले कारिगरों में वितरित किया। लेकिन स्वार्थी लोग इस पर भीूांत नहीं रहे। उन्होंने जमा की गई घास में आग लगाकर इस कार्य को व्यर्थ करने के प्रयास किये। दिशा ने भी अपने प्रयास जारी रखे। दिशा ने विकल्प, एक अन्य जमीनी स्तर की संस्था के सहयोग से रस्सी निर्माण करने वाले कारिगरों की एक संस्था बनाई और कारिगर सीधे ही कच्ची सामग्री खरीद सकते थे, इस प्रकार इन दोनों संस्थाओं ने कारिगरों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्त कराया।

ग्रामीण विकास के लिए कृ-ि में आजिविका सुधार और सामाजिक सुधारों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, किंतु समान्यतः इन्हें अलग कोने में फेंक दिया जाता है। पश्चिमी उत्तर-प्रदेश में आधारित 'दिशा' ग्रामीण आजिविका को बढ़ाने में प्रयास करती है और सामाजिक सुधारों के लिए भी कई प्रकार की पहल की है।

'जब प्रमुख लक्ष्य है कि लोगों का चहुंमुखी कल्याण करना तो मदीरा के उपभोग में कमी करने का प्रयास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कृ-ि में सुधार के लिए महत्वपूर्ण, लिंग समानता पर बल देने के प्रयास भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने बचत और छोटे उद्योगों को बचाने के लिए स्वयं सहायता समूह स्थापित करना। इनमें किसी एक क्षेत्र में प्रगति होने से अन्य क्षेत्र की भी प्रगति होगी', एक प्रमुख दिशा कार्यकर्ता जहानवी तिवारी का कहना है।

इस दृ-िकोण का एक संबंधित पहलू है, कमजोर वर्ग के लोगों को उच्च प्राथमिकता देना, अर्थात् छोटे कामगार और किसान मजदूर और इनके जैसे कारिगर। इसी वर्ग के अंतर्गत महिलाओं के अधिकारों और उन्हें नेतृत्व करने के अवसर प्रदान करने पर अत्यधिक बल देना। इस प्रकार की स्प-ट प्रमुखताओं को देखते हुए छोटे और मझौले किसानों का व्यापक स्तर पर एक मोर्चा बनाया गया है जिसमें दिशा के प्रमुख लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता के लिए हजारों किसान सदस्य भी बन गये। ऐसा करने से दिशा के सामाजिक सुधारों के लिए एक मजबूत प्लैटफॉर्म भी तैयार हो गया जिसका प्रमुख लक्ष्य सामाजिक समानता, लिंग औचित्य और सांप्रदायिक सदभाव बनाए रखना था, यही दिशा का मूल लक्ष्य है।

सुल्तानपुर जिले के सरसवा और सधौला कादिम ब्लॉक में लगभग 35 वर्-ा पहले दिशा संस्था का आरंभ हुआ, समय बितने के साथ अपना मूल लक्ष्य बनाते हुए दिशा ने पश्चिमी उत्तर-प्रदेश और पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के कई अन्य भागों में अपने कार्य फैलाए। दिशा का सार्वधिक महत्व सभी प्रयासों के लिए दिशानिदेश देते रहना है।

प्रारंभिक वर्-ों में स्वयं सहायता समूहों में महीलाएँ कैसे संगठित हुईं ? इन समूहों ने बहुत कम बचत से अपना कार्य प्रारंभ किया और समय बितने के साथ छोटी-छोटी बचतें इतने स्तर तक पहुंच गईं जहां से यह समूह महिलाओं को उधार राशि भी दे सकता था। महिलाओं ने अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने और छोटी दुकानें खोलकर, पट्टे पर भूमि लेकर अथवा भैंस खरीदकर अपनी आजिविका बढ़ाने के लिए ऋण लिया। इसके पश्चात इन समूहों का अधिक ऋण दिलाने के लिए बैंकों से भी लिंक करा दिया गया।

दिशा द्वारा स्थापित समूह एक मात्र प्रयास नहीं था, बल्कि उन्हें इकट्ठा करना भी था, क्योंकि वे अत्यधिक सामाजिक, आर्थिक वातावरण में पिछड़े हुए थे, परंतु फिर भी अपनी उत्कृ-ट कार्य प्रणाली के कारण उन्होंने पहचान बना ली। इनसे ऋण की वसूली अत्यधिक सराहनिय रही और इस कार्य के लिए नर्बोर्ड ने दिशा को

पुरस्कृत भी किया। यह समूह नियमित रूप से मिलते हैं और सामान्य हित और जन कल्याण के अन्य मामलों पर वार्तालाप भी करते हैं।

आखिरकार दिशा के कार्य को समेकित किया गया और अन्य क्षेत्रों में भी छोटे-छोटे ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये। इस संबंध में प्रश्न उठाए गये कि क्या दिशा संस्था ऐसे क्षेत्र में सफल हो पायेगी जिसका उसे कोई अनुभव या सामाजिक पृष्ठभूमि नहीं थी, ये दोनों क्षेत्र किसी भी नए उद्योग के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। फिर भी दिशा ने अपने कार्य का विस्तार करने के लिए विशेष प्रयास किये।

दिशा के संस्थापक समन्वयक के.एन. तिवारी कहते हैं कि इस संस्था का प्रमुख लक्ष्य कोई जोखिमपूर्ण अलग कारोबार करना नहीं है, बल्कि व्यापक कल्याण उद्देश्यों की प्राप्ति करना ही इसका प्रमुख कार्य और लक्ष्य है। फिर भी इस संस्था का विस्तार कार्य तब तक प्रगति पर था जब तक नोटबंदी लागू नहीं हुई थी। नोटबंदी के संबंधित पहलुओं के कारण इसका कार्य अत्यधिक प्रभावित हुआ। लेकिन लोगों को आशा है कि इस संकट से निपट लेंगे और उनके कार्य सुचारु ढंग से चलेंगे।

ऐसे क्षेत्रों में जहां विशिष्ट कृषि संबंधी सुधार कार्य आरंभ किये गये थे, वहां पर स्वयं सहायता समूहों के अतिरिक्त अलग किसान समूह बना दिये गये। इन प्रयासों से फसल विविधिकरण परियोजना के अंतर्गत आय कैसे बढ़ सकती है और कृषि क्षेत्र में लाभ और कैसे बढ़ सकता है, यदि हम फसलों की अलग-अलग किस्मों को सावधानी से चुनकर लगाएँ, यह जानकारी मिली। इस पहल के एक भाग के रूप में जैविक किसान पद्धतियों, कृषि रसायनिक पर निर्भरता में कमी एवम् लागत कम करने की विधियों को अपनाने पर जोर दिया गया।

उसी समय के आस-पास दिशा ने 2 अध्ययन (स्टडी) भी आयोजित कराए।

- पहला, कुछ गांव में किसानों की बढ़ती हुई समस्याएँ और कृषि-पारिस्थितिक संकट बदतर होता हुआ, विनय पर अध्ययन।
- दूसरा, आम के बगीचों पर परिवर्तित जलवायु का प्रभाव, विनय पर।

इस जांच परिणाम में पर्यावरण अनुकूल कृषि को अपनाने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। इस प्रकार भारत में जी.एम. फसलों के एक गंभीर मुद्दे पर बहस होने से पहले ही दिशा ने एक स्थानीय आयोजक के रूप में जी.एम. फसलों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करा लिया था, जिसमें इसके गंभीर परिणामों की चेतावनी दे दी गई थी। इस सम्मेलन में कई देशों के विशेषज्ञों ने भाग लिया था और एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित इस सम्मेलन की कार्यवाही से समयबद्ध चेतावनी दे दी थी।

दिशा संस्था ने कमजोर वर्गों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए भूमिहीन दलित किसानों को फसल उगाने के लिए भूमि वितरित की। इसके पश्चात प्रशासन ने कुछ भूमि को वापिस लेने का प्रयास किया तो दिशा ने तर्पता से कार्यवाही करते हुए विकल्प संस्था की सहायता से न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किये ताकि दलित किसानों के पास भूमि बनी रहे, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से उस भूमि को उपजाऊ बनाया था। यह दिशा - विकल्प दोनों का संयुक्त प्रयास था जिस कारण शिवालिक के रस्सी बनाने वाले कारिगरों को भी बिचौलियों के चंगुल से बचाने में सफलता प्राप्त की।

इसका कार्यक्षेत्र उत्तराखंड तक फैल चुका था तो दिशा ने टिहरी गढ़वाल जिले में कारिगरों की सहायता के प्रयास आरंभ किए। यहां दिशा ने अन्य कार्यों के अतिरिक्त भूकंप से प्रभावित लोगों के पुनर्वास में सहायता की। यमुना खादर क्षेत्र में दिशा ने एक अभियान चलाया जिस कारण वहां के प्रभावित उन हजारों किसानों को सरकार से राहत राशि उपलब्ध कराई, जिनके घर और भूमि जलभराव के कारण रहने के काबिल नहीं रह गई थी और वे बर्बादी के कगार पर थे।

दिशा का प्रमुख ध्यान महिलाओं के कल्याण पर केंद्रित था, क्योंकि महिलाओं ने दिशा संस्था के सभी कार्यों में बेहतर भागीदारी की थी और दिशा ने इसी कारण महिलाओं के सभी कार्यों में उन्हें नेतृत्व करने का अवसर दिया। एक अति संवेदनशील समय में जब कृषि मजदूर उच्च वेतन की मांग कर रहे थे तो दिशा और स्थानीय लोगों ने सबसे पहले महिला मजदूरों की मांगों पर जोर दिया, क्योंकि उन्हें अपने पुरुष मजदूरों की तुलना में कम वेतन दिया जाता था, जबकि महिलाएँ भी उनके जितना परिश्रम करती थी। यह एक अत्यंत कठिन संघर्ष था, किंतु अथक प्रयास करने के बाद महिला मजदूरों की मजदूरी में महत्वपूर्ण वृद्धि कराने में सफलता मिली।

विभिन्न पंचायत राज के निर्वाचनों और गांव के तृहरीकरण के लिए नगर समितियों के निर्वाचनों में भी महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया। दिशा ने नि-पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए अभियान चलाया ताकि ईमानदार उम्मीदवार चुने जा सकें। इसके अतिरिक्त इस संस्था ने कारगर महिला, विशेषकर कमजोर वर्ग की महिलाएँ, नेतृत्व को बनाने पर भी बल दिया और इस दिशा में कई कदम उठाए।

पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्वाचित महिलाओं को जब भी अच्छे ढंग से कार्यसंचालन की कोई सहायता की आवश्यकता पड़ी तो दिशा ने इन महिलाओं को सभी प्रकार की सहायता दी। उदाहरण के लिए सुल्तानपुर के चिलकाना गांव में लोग अब भी याद करते हैं कि सुरैया बेगम और रज्जौ दोनों निर्वाचित प्रतिनिधियों ने अत्यधिक प्रशंसनीय कार्य किए, जिसके लिए दिशा कार्यकर्ताओं ने उनकी सहायता की थी।

जब एक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि, जीनत को चुनाव में भाग लेने के लिए रूढ़िवादी लोगों ने अपमानित किया तो दिशा ने उनका विरोध करने में अग्रणीय भूमिका निभाई, जबकि उन कार्यकर्ताओं को इस विरोध के लिए बुरी तरह से पीटा भी गया।

महिलाओं को दी गई नेतृत्व की भूमिका से दिशा के एक लक्ष्य में भी सहायता मिली कि मदिरा निषेध पर भी बल दिया गया। हालांकि यह दिशा के निर्धारित कार्यों से संबंधित नहीं था, किंतु फिर भी इस संस्था की महिला सदस्यों ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई क्योंकि यह महिलाएँ अच्छी तरह जानती हैं कि जहां-जहां पर तृराब की दुकानें खोली गई हैं, वहां पर इसका अत्यधिक सेवन होने के कारण महिलाओं की ही कठिनाईयाँ और समस्याएँ बढ़ती हैं।

तृराब के सेवन से घर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार की आय कम होती है, घरेलू हिंसा बढ़ती है और गैर-सामाजिक तत्व तृराब की दुकानों के आस-पास इकट्ठे हो जाते हैं और महिलाओं की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है। यह मामला सहारनपुर जिले के पठेर गांव के प्रधान के सामने आया था, जहां पर समस्याओं में खतरनाक ढंग से वृद्धि हो चुकी थी।

इस गांव की महिलाओं ने यहां पर बनी टूराब की दुकान को हटाने की मांग करी और वे धरना प्रदर्शन पर बैठ गईं। दिशा ने गांव की महिलाओं को पूरा समर्थन दिया, किंतु यह एक अत्यंत कठिन कार्य था क्योंकि टूराब की दुकान का मालिक किसी राजनैतिक दल का नेता था और इस दुकान को बचाने के लिए कितना भी पैसा खर्च करने को तैयार था।

दिन से सप्ताह बित गए, किंतु यह मांग नहीं मानी गई। गांव वाले भी सीमित साधन होने के कारण धरना जारी रखने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। जिन महिलाओं ने इस धरने में अग्रणी भूमिका निभाई थी, उनके ही परिवार के पुरू- सदस्यों के विरोध का सामना करना पड़ा। यहां तक कि प्रशासन ने भी दिशा पर दबाव बनाया कि वह टूराब विरोधी आंदोलन का समर्थन करना बंद कर दे।

दिशा ने इस कार्य में तेजी दिखाई, दूसरी तरफ प्रशासन और असमाजिक तत्व भी तत्पर थे। अंत में महिलाओं के दृढ़ संकल्प, जिन्होंने इस निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्होंने संघर्ष जारी रखने का निर्णय लिया। स्थिति उस समय गंभीर हो गई, जब सहारनपुर में टूराब विरोधी आंदोलन में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बेरहमी से महिलाओं की भी पिटाई कर दी। कई महिलाएँ गंभीर रूप से घायल हुईं और उन्हें अस्तपाल में भर्ती कराना पड़ा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सब कुछ समाप्त हो गया, किंतु फिर भी धरना जारी रहा।

इसी बीच में इस आंदोलन की खबर उत्तर-प्रदेश के राज्यपाल को मिली, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया और भरोसा दिया कि टूराब की दुकान को हटा दिया जाएगा। इस खबर से पठेर गांव में स्वाभाविक रूप से उत्सव मनाया गया, और महिलाओं ने नृत्य किया तथा हलवाईयों ने मुफ्त में ही मिठाईयां बांटी।

महिलाओं और कार्यकर्ताओं के मजबूत समूह ने दिखा दिया की वे किसी भी प्रकार के भय और दमन से रुकने वाले नहीं हैं, और दिशा संस्था ने इस चुहुंमुखी दबाव में भी अपना उत्साह बनाए रखा तथा टूराब विरोधी कार्य में पूरा समर्थन और सहायता प्रदान की। इस घटना के माध्यम से यह भी साबित हुआ कि सामाजिक परिवर्तन, सुधार और सभी स्तरों पर समानता लाने में दिशा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

दलितों के विरुद्ध भेदभाव का विरोध करने में दिशा प्रमुख रूप से एक सक्रिय संस्था है। कुछ वरि-ठ सदस्यों ने बताया कि पुरानी परंपराएँ और लोगों की पुरानी सोच को तोड़ना कितना कठिन कार्य था। दलित परिवारों के लिए भी प्रारंभ में यह अत्यंत कठिन कार्य था कि वे अपनी बिरादरी के सदस्यों को भी समान रूप से स्वीकार करें। समय बीतने के साथ-साथ यह सोच बदली और लोग सभी स्तरों पर सामाजिक समानता की आवश्यकता के प्रति सहमत हो चुके हैं। जहां पर दिशा संस्था के कार्यकर्ताओं ने कार्य किए वहां के गांव में इसका व्यापक और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

दिशा संस्था की दार्शनिकता और कार्य प्रणाली का केन्द्र बिंदु सामाजिक सदभाव है; इसके संचालन कार्यों में हिन्दु और मुस्लिम दोनों की मिश्रित संख्या है। इन दोनों समुदायों में अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए दिशा संस्था निरंतर प्रयास कर रही है। यह संस्था दोनों समुदायों के सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से ईद और होली मनाते हैं। दिशा कार्यकर्ता दोनों ही समुदायों से संबंध रखते हैं और पारस्परिक विश्वास और सहयोग से कार्य करते हैं। उनके उदाहरण से अन्य गांव में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

सुल्तानपुर के चिलकाना में जब दिशा ने कार्य आरंभ किया तो उस समय ग्रामीण समाज पंडित और मीर दो गुटों में बंटा हुआ था। कमजोर वर्ग की कम पहुंच होने के कारण कोई स्वतंत्र पहचान नहीं थी, सभी वर्गों में सदभाव पूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए दिशा ने छोटे और मझौले किसानों, भूमिहीन मजदूरों और अन्य कमजोर वर्गों के लोगों को व्यापक सहयोग दिया, जिसमें महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी चुनी गई।

इन कार्यों और प्रयासों का परिणाम यह आया कि इन वर्गों से संबंधित अधिकतम लोगों की स्वतंत्र पहचान बनी जो भाईचारे और सामाजिक कल्याण पर आधारित थी, इसके अतिरिक्त भेदभाव व पक्षपात और पृथक्करण दूर हुआ। कुछ ही वर्गों में सभी प्रकार के भेदभाव और पक्षपात दूर करना संभव नहीं है, फिर भी सामाजिक समानता की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सामाजिक कल्याण से संबंधित विकास कार्यों की सफलता के लिए इस प्रकार की सामाजिक समानता लाने का मूल कार्य करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

जब इस महत्वपूर्ण कार्य को छोड़ते हुए केवल परियोजना के विकास पहलू को प्राथमिकता दी जाती है तो ऐसी परियोजनाओं की सफलता और उनका औचित्य निर्धारित करते हुए अन्य समुदायों के मन में यदि कोई टूटका रह गई तो इस प्रकार की कोई भी योजना असफल हो जाएगी, यदि सबसे पहले सामाजिक समानता की नींव नहीं रखी गई। इसी कारण बहुमुखी अनुभव सीखने के लिए दिशा ने इसी विशिष्ट क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है।

दिशा संस्था की तीन महिला कार्यकर्ता एक दूरस्थ गांव से बस से वापिस थकी और प्यासी लौट रही थी और वे तृप्त पेय पीना चाहती थी। उनके पास तीन तृप्त पेय खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने तृप्त पेय खरीदा और तीन पाईपों से वे तीनों पीने लगीं। जब वे इकट्ठी तृप्त पेय का सेवन कर रही थीं तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि इनमें से एक ब्राह्मण, एक दलित और एक मुस्लिम है।

उन्होंने प्रशंसापूर्वक हां में उत्तर दिया; 'हां, दिशा संस्था निःसंदेह समानता और सामंजस्य पर आधारित नया समाज बनाने के लिए दिशा दर्शाती है।'